श्रमेव जयते

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक),बिहार

INDIAN NATIONAL TRADE UNION CONGRESS, BIHAR

पंत्राक-

दिनांक-

## केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 09 अगस्त, 16 को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह (अवज्ञा आन्दोलन) के अन्तर्गत प्रदर्शन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**

.....

विषयः- दिनांक- 09 अगस्त, 2016 को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों का देशव्यापी सत्याग्रह के अनतर्गत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन/धरना।

महाशय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुये कहना है कि देश के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से 12 सूत्री मांगों (संलग्न) की पूर्ति हेतु दिनांक- 09 अगस्त, 2016 को सत्याग्रह (अवज्ञा आन्दोलन) का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत देश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि देश के सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से केन्द्र सरकार को 12 सूत्री मांगों की सूची समर्पित किया है, जिसकी पूर्ति हेतु दिनांक- 02 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है।

### केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा प्रेषित मांगों की सूची।

1. स्थायी/बारहमासी प्रकृति के कार्यो को ठीका पर नहीं देना तथा संविदा पर कार्यरत मजदूरों को उद्योग/संस्थान के नियमित कर्मचारियों के समतुल्य समान कार्य - समान वेतन एवं अन्य सुविधाओं दी जाये।
2. अनुसूची को बिना आधार बनाये सभी नियोजनों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जाये, जो वर्तमान में 15000/- (पन्द्रह हजार) रूपये से कम न हो।
3. भविष्य निधि एवं बोनस के लिए पात्रता एवं भुगतान पर लगी सीमाओं को समाप्त करना तथा ग्रेच्यूटी भुगतान की 15 दिन प्रतिवर्ष की सीमा को बढ़ाना।
4. पेंशन का लाभ सभी को देना सुनिश्चित करना।
5. रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को मजबूती से लागू करना।
6. श्रम कानूनों का अनुपालन तत्परता के साथ हो एवं विभिन्न क्षेत्रों/कारखानों एवं संस्थानों में हो रहे उलघ्घन के विरूद्ध कड़ी कारवाई सुनिश्चित करना।
7. असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने एवं इसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन करना।
8. श्रमिक संघों का निबंधन 45 दिनों के अन्दर अनिवार्य करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के कन्वेंशन 87 एवं 98 को अविलम्ब रेटिफाई (सम्पुष्ट) करना।
9. मूल्य वृद्धि (मंहगाई) को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना एवं जन वितरण प्रणाली के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ना।
10. केन्द्रीय तथा राज्यो के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी विनिवेश की प्रक्रिया को रोकना।
11. रेलवे, डिफेंस एवं अन्य दक्ष/निपुण क्षेत्रों में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) न हो।
12. श्रम कानूनों में एकतरफा संशोधन बन्द करो।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा इन 12 सूत्री मांगों के अतिरिक्त दिल्ली में हुई कन्वेंशन दिनांक- 26 मई, 2015 में कुछ और बिन्दुओं पर चर्चा हुई है, जो निम्नलिखित है :-

- स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना।
- फुटपाथ दुकानदारों/स्ट्रीट वेन्डर्स के कानून को शक्ति से लागू करो एवं दूकान हटाने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था करो।

### स्थानीय मांगें।

जिला कमिटी अपने स्तर से इसमें अन्य स्थानीय मांगें जोड़ सकती है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने स्तर से राज्य/केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन